Health Programmes were identified after due consideration by the Director General of Health Services and recommended by the Ministry of Health and F.W. to the Department of Chemtotak for price control under category I of the DPCO, 1987. Drugs for 3 other identified National Health Programmes are being evaluated for price control recommendations,

Byepass on National Highway No. 47

3978. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the length of Trivandrum-Neytinakara byepass on NH 47;

(b) what amount has been allotted therefor, so far;

(c) what amount has been spent so far;

(d) by when the byepass is expected to be ready as per schedule;

(e) whether it would be ready for traffic as per schedule if not, what are the reasons therefor; and

(f) what amount of more funds are required for it and whether it would be sanctioned?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) 43 Kilometres.

(b) and (c) An expenditure of Rs. 6.40 crores has been incurred upto 31.3.88. The expenditure during the current year is to be met out of the allocation of Rs. 10 crores for development of National Highways in Kerala.

(d) to (f) The work is being taken.up in two phases. A short length of about 1.18 kms. in phase I has been completed and opened to traffic. The work in two other stretches (about 5.0 km. in lenglth) of phase-I is in progress. Phase II is in planning stage and it is too early to indicate the date of completion and the amount required.

Pay scales of ISM and Homoeopathy physicians recommended by Fourth Pay Commission

3979. DR. G. V1JAYA MOHAN REDDY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what are the different scales of pay which have been recommended by the Fourth Pay Commission for diploma and degree holders of ISM and Homoeopathy physicians in the C.G.H.S.;

(h) whether Government have accepted these pay scales;

(c) whether Government have received any representation from physicians belonging to this category for the early implementation of the Fourth Pay Commission's recommendations; and

(d) if so, what are the details thereof and what actios Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) to (d) The Fourth Pay Commission have recommended a pay scale of Rs 2000—3500 for diploma and pay scale of Rs. 2200-1000 for degree holders ISM and Homoeopathy physicians in CGHS. The Joint Action Committee have given a memorandum and have drawn the attention of the Goveernment to the disparities in the pay scales recommended by the Fourth) Pay Commission for degree and diploma holders ISM and Homoeopathy physicians. The major demand of the Joint Action Committee is that the pay scales promotional avenues, NPA and other privileges that are being given to allopathic doctors should also be made applicable to them. The recommendations of the Fourth Pay Commission are under consideration and a final decision will be taken after due consultation with all concerned.

Delay in the appointment of dean in AIIMS

3980. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to to state:

(a) whether there has been an inordinate delay in the appointment of a new dean

in the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a and (b) The post of Dean, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi fell vacant on the 30th April, 1988 on the superannuation of Prof. O. P. Ghei. Prof. M. M. S. Ahuja was appointed as Dean on the 27th May, 1988 on a temporary basis which was regularised on 6-7-1988.

रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें

3981. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेल कर्मियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अभद्र व्यवहार तथा अन्य गैर-कानूनी कार्य करने के कितने मामले प्रकाश में आये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) दिन-प्रतिदिन रेल कर्मियों के बढ़ते हुए अभद्र व्यवहार को रोकने के लिए क्या कोई अभियान चलाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) यथा सम्भव उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) जी हां। कदाचार को रोकने के लिए रेल प्रशासन निरन्तर प्रयासरत रहता है। यह कहना सही नहीं है कि रेल कर्मचारियों का रेल उपयोगकर्ताओं के प्रति दुर्व्यवहार बढ़ रहा है। जनता को स्टेशनों पर शिकायत पुस्तिका की उपलब्धता, जन शिकायत संगठन और सतर्कता संगठन के पतों की सूचना समय-सारणी और स्टेशन पर लगे नोटिसों के माध्यम से दी जाती है। रेल उपयोगकर्ताओं के रेल कर्मचारियों के सौहार्दपूर्ण व्यवहार को बहुत महत्व दिया जाता है। इस दिशा में सुधार लाने के लिए जनता के सीधे सम्पर्क में आने वाले कर्मचारियों पर रेल उपयोगकर्ताओं के साथ ठीक ढंग से तथा सेवाभाव से व्यवहार करने पर और जोर देने के लिए नियमित अन्तरालों पर सौहार्द सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। सौहार्दता को प्रशिक्षण स्कूलों के प्रारंभिक और अभिविन्यास दोनों पाठ्यक्रमों में कर्मचारियों के पाठ्यक्रम की एक मद के रूप में शामिल किया गया है। कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए उच्चतर ग्रेडों में रखी जाने वाली गोपनीय रिपोर्टों में जनता के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार को एक मद के रूप में रखा गया है।

दिल्ली परिवहन निगम का किराये में वृद्धि करने का प्रस्ताव

3982. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 11 मई, 1988 को राज्य सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न 1880 के उत्तर को देखने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1986 में किरायों में वृद्धि किए जाने के बावजूद भी दिल्ली परिवहन निगम घाटे में चल रहा है; और

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम में इस घाटे का मुख्य कारण उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है और इस किराया वृद्धि से निगम का घाटा समाप्त नहीं होगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। दिल्ली परिवहन निगम को मुख्यत: अपने प्रचालन पर फरवरी, 1986 में संशोधन के बावजूद अलाभकर भाड़ा ढांचे के कारण घाटा हो रहा है। इस संशोधन से कार्य संचालन घाटे की आंशिक पूर्ति ही हुई है।

दिल्ली में मान्यता प्राप्त स्कूल

3983. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :